

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका सिरीज
Question Booklet Series

A

B.A.LL.B (Fourth Semester) Examination, January-2022

B.A.LL.B404 (PAPER-IV)

ADMINISTRATIVE LAW

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
 2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
 3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
 4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
 5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
 6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक—पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
 7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।

1. The reasons for the growth of administrative law is-
 - (A) Social-welfare nature of the state
 - (B) Technological advancement and industrialization
 - (C) Lack of time for parliament to carry its usual functions
 - (D) All the above
2. Which among the following is not the reason for the growth of administrative law-
 - (A) Technical nature of modern legislation
 - (B) Transformation of state from 'Police state' to 'Social welfare state-
 - (C) Fairness of administration
 - (D) Making emergency provisions for famine and natural calamities
3. Who among the following gave this definition of administrative Law?

"Administrative Law is the law relating to administration. It determines to organization, powers and duties of administrative authorities."

 - (A) Wade and Philips
 - (B) Sir Ivor Jennings
 - (C) K.C. Davis
 - (D) Prof. M.P. Jain
4. Administrative Law is the functional side of-
 - (A) Constitutional Law
 - (B) Civil Law
 - (C) Criminal Law
 - (D) Law of Trot

1. प्रशासनिक विधि के विकास का कारण है-
 - (A) राज्य की समाज-कल्याणकारी प्रकृति का होना
 - (B) तकनीकी अभिवर्धन एवं औद्योगीकरण
 - (C) संसद के पास अपने सामान्य कार्यों को संपादित करने में समय का अभाव
 - (D) उपरोक्त सभी
2. निम्न में से कौन प्रशासनिक विधि के विकास का कारण नहीं है-
 - (A) वर्तमान विधायन का तकनीकी प्रकृति का होना
 - (B) राज्य का संपरिवर्तन 'पुलिस राज्य' से 'समाज-कल्याणकारी राज्य' में होना
 - (C) प्रशासन का न्यायसम्यक होना
 - (D) अकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं हेतु आकस्मिक प्रावधान बनाना
3. निम्न में किसके द्वारा प्रशासनिक विधि की यह परिभाषा दी गई है?

"प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के गठन शक्तियों तथा कर्तव्यों का अवधारण किया जाता है।"

 - (A) वेड एवं फिलिप्स द्वारा
 - (B) सर आइवर जेनिंग्स द्वारा
 - (C) के०सी० डेविस द्वारा
 - (D) प्रो० एम० पी० जैन द्वारा
4. प्रशासनिक विधि एक क्रियात्मक पक्ष है-
 - (A) संवैधानिक विधि का
 - (B) सिविल विधि का
 - (C) दाण्डिक विधि का
 - (D) अपकृत्य विधि का

- | | |
|--|--|
| <p>5. Administrative Law falls in the branch of -
 (A) Public law
 (B) Private law
 (C) Both public and private law
 (D) In none of the above</p> <p>6. The scope of administrative laws intends to-
 (A) Central and state Tribunals
 (B) Administrative Decision
 (C) Quasi-judicial functions of administrative authorities
 (D) To all the above</p> <p>7. Who among the following did not the existence of administrative law in England?
 (A) A.V. Dicey
 (B) Maitland
 (C) Ivor Jennings
 (D) Blackstone</p> <p>8. The fundamental principle of administrative law is-
 (A) Power corrupts and absolute power corrupts absolutely
 (B) The power vested in administrative authorities should not be unlimited
 (C) Adequate controls should be placed of powers exercised by administrative authorities
 (D) All the above are true</p> <p>9. The king can do know wrong, long live the king". This statement in English law -
 (A) Supports administrative law
 (B) Negates administrative law
 (C) Partially supports and partially negates administrative law
 (D) None of the above</p> | <p>5. प्रशासनिक विधि, विधि की किस शाखा में आती है—
 (A) लोक विधि में
 (B) प्राइवेट विधि में
 (C) लोक एवं प्राइवेट विधि दोनों में
 (D) उपरोक्त में से किसी में नहीं</p> <p>6. प्रशासनिक विधि का क्षेत्र विस्तीर्ण होता है—
 (A) केन्द्रीय एवं राज्य न्याधिकरणों
 (B) प्रशासनिक निर्णयों पर
 (C) प्रशासनिक अधिकारियों के अर्द्धन्यायिक कार्यों पर
 (D) उपरोक्त सभी पर</p> <p>7. निम्न में से किसने इंग्लैंड में प्रशासनिक विधि के अस्तित्व को नकारा था?
 (A) ऐ० वी० डॉयसी ने
 (B) मेटलैंड ने
 (C) आइवर जेनिंग्स ने
 (D) ब्लैकस्टोन ने</p> <p>8. प्रशासनिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है—
 (A) शक्ति भ्रष्ट करती है और आत्यांतिक शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है
 (B) प्रशासनिक अधिकारियों में निहित शक्तियाँ असीमित नहीं होनी चाहिए
 (C) प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त शक्तियों पर पर्याप्त नियन्त्रण होने चाहिए
 (D) उपरोक्त सभी सही है</p> <p>9. "राजा कोई पाप नहीं कर सकता, राजा चिरायु रहे।" यह कथन आँग्ल विधि में—
 (A) प्रशासनिक विधि को समर्थित करता है
 (B) प्रशासनिक विधि को नकारता है
 (C) आंशिक रूप से समर्थन करता है तथा आंशिक रूप से नकारता है
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <p>10. In ancient India the main basis of administrative law was-</p> <p>(A) Principle of Dharma</p> <p>(B) Preaching of seers</p> <p>(C) King's command</p> <p>(D) All the above</p> | <p>10. प्राचीन भारत में प्रशासनिक विधि का प्रमुख आधार था—</p> <p>(A) धर्म का सिद्धान्त</p> <p>(B) महर्षियों के उपदेश</p> <p>(C) राजा का समादेश</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>11. The whole foundation of administrative law is based fundamentally on the principle of-</p> <p>(A) Rule of law</p> <p>(B) Separation of powers</p> <p>(C) Supremacy of the constitution</p> <p>(D) Public opinion</p> | <p>11. प्रशासनिक विधि का संपूर्ण आधार मूलतः जिस मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है, वह है—</p> <p>(A) विधि का शासन</p> <p>(B) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त</p> <p>(C) संविधान की सर्वोच्चता</p> <p>(D) लोकमत</p> |
| <p>12. The original propounder of the concept of 'Rule of law was -</p> <p>(A) Jeremy Bentham</p> <p>(B) A.V. Dicey</p> <p>(C) Edward Coke</p> <p>(D) John Stuart Mill</p> | <p>12. 'विधि के शासन' की अवधारणा के मूल प्रतिपादक थे —</p> <p>(A) जेर्मी बेन्थम</p> <p>(B) ऐ० वी० डायसी</p> <p>(C) एडवर्ड कोक</p> <p>(D) जॉन स्टुअर्ट मिल</p> |
| <p>13. A.V. Dicey's Book which contains the principle of Rule is -</p> <p>(A) Law of the constitutions</p> <p>(B) British law of the constitutions</p> <p>(C) Constitutional process</p> <p>(D) Law and the constitution</p> | <p>13. ए० वी० डायसी की वह पुस्तक जिसमें 'विधि के शासन' के सिद्धान्त का उल्लेख है वह है—</p> <p>(A) "संविधानों की विधि"</p> <p>(B) संविधान की ब्रिटिश विधि</p> <p>(C) संवैधानिक प्रक्रिया</p> <p>(D) विधि एवं संविधान</p> |
| <p>14. Dicey's concept of rule of law supports-</p> <p>(A) Supremacy of the law</p> <p>(B) Equality before law</p> <p>(C) Omnipotence of the spirit of law</p> <p>(D) All the above</p> | <p>14. डायसी की 'विधि के शासन' की संकल्पना समर्थन करती है—</p> <p>(A) विधि की सर्वोच्चता की</p> <p>(B) विधि के समक्ष समता की</p> <p>(C) विधि की भावना की सर्वव्यापकता की</p> <p>(D) उपरोक्त सभी का</p> |

15. 'Recognition of Individual rights under the constitution is not that of much importance unless and until machinery for their enforcement through court is present.' This view is attributable to -
 (A) Locke
 (B) Dicey
 (C) Blackstone
 (D) Edward Coke
16. Dicey's concept of rule of law finds place under the Indian constitution in Article-
 (A) 21 of the constitution
 (B) 16 of the constitution
 (C) 14 of the constitution
 (D) 15 of the constitution
17. Point out the incorrect option- Dicey's concept of Rule of law is-
 (A) Against wide discretionary powers to administrative authorities
 (B) Negates rule of men to rule by law
 (C) Enact equivalent of the concept in equality before law
 (D) Supportive of supremacy of law
18. Which is the main drawback of Dicey's concept of rule of law?
 (A) Failure to distinguish between arbitrary power and discretionary power
 (B) Equating discretionary power with arbitrariness
 (C) Both (A) and (B) are true
 (D) It favored rule by law over rule by men
15. "किसी संविधान में वैयक्तिक अधिकारों का समावेश मात्र कोई ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान धारण नहीं करता जबतक उनके प्रवर्तन के लिए न्यायालय की मशीनरी उपलब्ध न हो।" यह मत है—
 (A) लॉक का
 (B) डॉयसी का
 (C) ब्लैकस्टोन
 (D) एडवर्ड कोक का
16. डायसी की संकल्पना भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में जगह प्राप्त करती है, वह है—
 (A) संविधान का अनुच्छेद 21
 (B) संविधान का अनुच्छेद 16
 (C) संविधान का अनुच्छेद 14
 (D) संविधान का अनुच्छेद 15
17. गलत विकल्प को चुने—
 डायसी की विधि के शासन की अवधारणा—
 (A) प्रशासनिक अधिकारियों को विस्तृत स्वविवेकीय शक्तियों को देने के विरुद्ध हैं।
 (B) व्यक्तियों के शासन को नकारते हुए विधि के द्वारा शासन को बढ़ाती है
 (C) "विधि के समक्ष समता" संकल्पना की पूर्ण समतुल्य अवधारणा है
 (D) विधि की सर्वोच्चता को समर्थन करती है
18. डॉयसी की 'विधि का शासन' को संकल्पना का मुख्य दोष यह है—
 (A) मनमानी शक्ति तथा स्वविवेकीय शक्ति में अन्तर न कर पाना
 (B) स्वविवेकीय शक्ति को स्वेच्छाचारिता के समतुल्य मानना
 (C) (A) और (B) दोनों सही हैं
 (D) कि यह विधि को सर्वोच्चता को समर्थित करता है

19. Point out the incorrect option-
Dicey's concept of rule of law in modern times is-
- (A) Followed by the most democratic countries
 - (B) Both Parliamentary and presidential's systems of Governance recognize it in varying degree
 - (C) Communists Government's also follow rule of law
 - (D) Best antidote for administrative arbitrariness
20. The book 'Spirit of Laws' was written by-
- (A) Plato
 - (B) Montasque
 - (C) Aristotle
 - (D) Roussaeu
21. The principle of "Separation of powers" was for the first systematically and scientifically organized by-
- (A) Montesque
 - (B) Justice Cordozo
 - (C) Jean Bodin
 - (D) Nietze
22. French Legal system is known as -
- (A) Conseil d'etat
 - (B) Droit administratif
 - (C) Judex administratif
 - (D) None of the above

19. गलत विकल्प को चुने-
डायसी के विधि के शासन की संकल्पना वर्तमान में-
- (A) सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा अनुसरण की जाती है
 - (B) शासन की संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली भिन्न भिन्न मात्रा में इस सिद्धान्त को मान्यता देते हैं
 - (C) कम्युनिस्ट सरकारें भी विधि के शासन का अनुसरण करती हैं
 - (D) प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध यह सबसे बढ़िया प्रतिषेधक दवा है
20. "विधियों की भावना" पुस्तक के रचयिता थे-
- (A) प्लेटो
 - (B) मोन्टेस्क्यू
 - (C) अरस्तू
 - (D) रूसो
21. 'शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त' को सर्वप्रथम पर व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया था-
- (A) मोन्टेस्क्यू द्वारा
 - (B) जस्टिस कॉर्डोजो द्वारा
 - (C) जीन बोदिन द्वारा
 - (D) नीत्से द्वारा
22. फ्रान्स की विधिक व्यवस्था को कहते थे-
- (A) काउन्सिल डि-इटेट
 - (B) ड्रॉयट एडमिनिसट्रेटिफ
 - (C) ज्यूडेक्स एडमिनिसट्रेटिफ
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. Doctrine of separation of power means-
- (A) Each organ of the Government should have only one power
 - (B) One organ of the government should not encroach upon the powers of other
 - (C) One organ of the government should not perform functions of the organ
 - (D) All the above are correct
24. "Montesquieu looked across foggy England from his sunny Vineyard in Paris and completely misconstrued what he saw". The statement is a -
- (A) Criticism of Montesquieu Theory of absolute separation of powers among the organs of the government
 - (B) Supports theory of separation of powers
 - (C) Supports the view that in England there existed no system of separation of powers
 - (D) Both (A) and (C) are true
25. Point out the incorrect option- Doctrine of separation of powers-
- (A) Advocates decentralization of powers in various organs of the Government
 - (B) Advocates its parallel existence in all legal systems along with rule of law
 - (C) Checks the encroachment of powers of one organ by other through system of check and balance
 - (D) Is not in existence in any Nation in absolute terms
23. 'शक्ति पृथक्करण' सिद्धान्त से तात्पर्य है कि—
- (A) सरकार के प्रत्येक के पास केवल एक शक्ति ही होनी चाहिए
 - (B) सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों का अतिक्रमण न करे
 - (C) सरकार का एक दूसरे अंग के कार्यों को न करें
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
24. 'मोन्टेस्क्यू ने पेरिस स्थित प्रकाशमान अपने अंगूर के बगीचे से धुंधयुक्त इंग्लैण्ड को देखा और जो देश उसका पूर्णतया गलत आकलन किया।' यह कथन—
- (A) मान्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के द्वारा शक्तियों के तीनों अंगों में आत्यांतिक वितरण की आलोचना है
 - (B) शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का समर्थन करता है
 - (C) इस मत का समर्थन करता है कि इंग्लैण्ड में कभी भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त अस्तित्व में था
 - (D) (A) और (C) सही है
25. गलत विकल्प को चुने— 'शक्ति पृथक्करण' का सिद्धान्त—
- (A) सरकार के सभी अंगों में शक्ति विकेन्द्रण का समर्थन करता है
 - (B) सभी विधिक व्यवस्थाओं में अपना अस्तित्व समान्तर रूप से 'विधि के शासन' के साथ मानता है
 - (C) सरकार के अंग द्वारा दूसरे के कार्यों में अतिक्रमण को 'चेक एवं बैलेन्स' के आधार पर नियन्त्रित करता है
 - (D) किसी भी राष्ट्र में अपने आत्यांतिक रूप में विराजमान नहीं है

26. Most distinguished writers of administrative law agree that in strict sense doctrine of separation of powers-
- (A) Is undesirable and impracticable advocates not
 - (B) Advocates that functions of legislature, Executive and Judiciary are independent of each other which is a fallacy
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) Both (A) and (B) are false
27. The doctrine of separation of powers is applicable in limited form in all legal systems in the sense-
- (A) Judiciary should always be independently separated from Executive and legislative wing
 - (B) There is an over lapping of legislative and Executive function in all systems of governance
 - (C) Only legislative should be free from influence of both executive and judiciary
 - (D) Only (A) and (B) are true
28. The majority opinion in A.D.M Jablapur Vs Shivakant Shukla case-
- (A) Supported Rule of law in its true sense
 - (B) Gave a very narrow view of Rule of law
 - (C) Diametrically opposite of minority opinion
 - (D) Both (B) and (C) are true
26. प्रशासनिक विधि के सभी प्रतिष्ठित लेखक इस बात पर सहमत हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपने कठोर रूप में-
- (A) अवांछनीय और अव्यवहारिक है
 - (B) यह अवधारित करता है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं जो कि त्रुटि है
 - (C) दोनों (A) और (B) सही हैं
 - (D) दोनों (A) और (B) गलत हैं
27. 'शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त सीमित रूप में सभी विधिक व्यवस्थाओं पर लागू हैं इस अर्थ में कि-
- (A) न्यायपालिका को सदैव कार्य पालिका तथा विधायिका से स्वतन्त्र रूप से अलग रखा जायें।
 - (B) सभी शासन प्रणालियों में कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों में आच्छादता रहती है
 - (C) केवल विधायिका को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से स्वतन्त्र रखा जायें
 - (D) केवल (A) और (B) सही हैं
28. ए०डी०एम० जबलपुर बनाम शिवाकान्त शुक्ला के वाद में बहुमत ने-
- (A) 'विधि के शासन' का समर्थन उसके वास्तविक स्वरूप में किया
 - (B) 'विधि के शासन' को बहुत संकीर्ण निवर्चन प्रदान किया
 - (C) अल्पमत का ठीक विपरीत था
 - (D) दोनों (B) और (C) सही हैं

29. The Article of the Indian constitution which supports 'doctrine of separation of powers' in partial form is-
- Article 44
 - Article 50
 - Article 51
 - Article 40
30. the doctrine of "Separation of powers" as propounded by Montesquieu was based on his experiences with-
- British Legal system
 - American Legal system
 - France's Legal system
 - Both American and French Legal System
31. "The Law making power is vested in the Legislature alone" Delegated legislation is-
- An exception to above stated rule
 - Is an extension of above rule
 - Part and parcel of Legislative power
 - Valid always
32. "When the function of legislation is entrusted to organs other than the legislature by the legislature itself then the legislation made by such organs is called-
- Deemed legislation
 - Delegated legislation
 - Legislation with a difference
 - Parallel legislation
29. भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 'शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त' का आंशिक समर्थन करता है वह है—
- अनुच्छेद 44
 - अनुच्छेद 50
 - अनुच्छेद 51
 - अनुच्छेद 40
30. मोन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित "शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त" जिस विधिक व्यवस्था के अनुभवों पर था, वह थी—
- ब्रिटिश विधिक व्यवस्था
 - अमेरिकन विधिक व्यवस्था
 - फ्रांस की विधिक व्यवस्था
 - अमेरिकी तथा, फ्रांस की विधिक व्यवस्था पर
31. "विधि निर्माण की शक्ति केवल विधायिका में निहित है।" प्रत्यायोजित विधायन है—
- उपरोक्त वर्णित नियम का अपवाद
 - उपरोक्त वर्णित नियम का विस्तार
 - विधायी शक्ति का अभिन्न भाग है
 - सदैव विधिमान्य
32. जब विधायन का कार्य स्वयं विधायिका द्वारा विधायिका के अतिरिक्त अन्य अंगों को सुपुर्द किया जाता है तो ऐसे अंग द्वारा निर्मित विधायन कहलाता है—
- समतुल्य विधायन
 - प्रत्यायोजित विधायन
 - अन्तर के साथ विधायन
 - समान्तर विधायन

33. Delegated legislation includes -
(A) All rules made by a delegate
(B) Regulations and bye-laws made by a delegate
(C) Orders or notification issued by the delegate
(D) All the above

34. Point out the incorrect option out of the following-
“Delegates non potest delegare” means
(A) A delegate cannot further delegated powers vested in him
(B) There is no prohibition for further delegation of powers by the delegate
(C) Delegated powers must be exercised by the delegate himself
(D) Delegated powers cannot be extended to other authorities by the delegate

35. The reason for the growth of delegation legislation is-
(A) End of the traditional principle of laissez-faire
(B) Establishment of a social welfare state in place of police state
(C) Pressure on legislative functions
(D) All the above are true

33. प्रत्यायोजित विधायन में सम्मिलित है -
(A) प्रतिनिधि द्वारा बनाये गये सभी नियम
(B) प्रतिनिधि द्वारा बनाए गये सभी रेग्यूलेशन एवं उपनियम (विनियम)
(C) प्रतिनिधि द्वारा निर्गत आदेश अथवा अधिसूचना
(D) उपरोक्त सभी

34. निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें-
“डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे” का अर्थ है-
(A) एक प्रतिनिधि अपने को प्रत्यायोजित शक्तियों का पुनर्प्रत्यायोजन नहीं कर सकता
(B) प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के पुनर्प्रत्यायोजन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है
(C) प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग केवल प्रतिनिधि द्वारा ही किया जाना चाहिए
(D) प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार अन्य प्राधिकारियों पर प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जा सकता है

35. प्रशासनिक विधि के विकास का कारण है-
(A) यथास्थितिवाद के परंपरागत सिद्धान्त की समाप्ति
(B) पुलिस राज्य के स्थान पर समाज-कल्याणकारी राज्य की स्थापना
(C) विधायिनी कार्यों पर दबाव
(D) उपरोक्त सभी सत्य है

36. The factor which is not responsible for growth of delegated legislation is-

- (A) Technical nature of modern legislation
- (B) Multifarious increase in the functions of the state
- (C) Non-participation of elected representatives in debates and absenteeism for political reasons in legislature
- (D) None of the above

37. The first pre-constitutional case of delegated legislation was that of -

- (A) Queen Vs Burah
- (B) Jatindra Nath Gupta Vs Province of Bihar
- (C) Panama Refining Co. Vs Ryan
- (D) None of the above

38. Point out correct option in Re Delhi Laws Act, 1912 case the Supreme Court of India held that-

- (A) Legislative powers can be delegated keeping in view the exigencies moderntimes
- (B) A Delegate does not stand on the same footing as parliament
- (C) Delegation of legislative power with restriction is permissible
- (D) All the above are correct

36. वह कारक जो प्रशासनिक विधि के विकास के लिए सहयोगी (उत्तरदायी) नहीं है, वह है—

- (A) आधुनिक विधायन का तकनीकी होना
- (B) राज्य के कार्यों में बहुतायात में अभिवृद्धि
- (C) चुने गये प्रतिनिधियों का परिचर्चाओं में सम्मिलित न होना तथा विधायका में राजनैतिक कारण से अनुपस्थित रहना
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

37. संविधान पूर्व प्रथम वाद जो प्रत्यायोजित विधायन से संबंधित था, वह है —

- (A) क्वीन बनाम बुराह
- (B) जतीन्द्र नाथ गुप्ता बनाम बिहार प्रान्त
- (C) पनामा रिफाइनिंग कं० बनाम रेयान
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

38. सही विकल्प का चयन करें—

री देहली लॉज एक्ट, 1912 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया—

- (A) वर्तमान समय की अपरिहार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है
- (B) एक डेलीगेट की स्थिति संसद के समतुल्य नहीं है
- (C) विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन निर्बन्धों के साथ हो सकता है
- (D) उपरोक्त में से सभी सही है

39. As per in Re Delhi laws act case the legislature can-

- (A) Delegate its essential legislative powers
- (B) Cannot delegate its essential legislative power
- (C) Only ancillary legislative power can be delegated
- (D) Both (B) and (C) are correct

40. The function of the Executive can be classified as-

- (A) Discretionary functions
- (B) Quasi-judicial functions
- (C) Delegated legislative functions
- (D) In All of the above

41. Which of the functions cannot be delegated by the legislature?

- (A) Commencement of the act
- (B) Inclusion and exclusion clause
- (C) Application of the existing laws
- (D) Essential legislative functions

42. Which of the following is not a control on delegated legislation-

- (A) Doctrine of Ultra vires
- (B) Judicial control
- (C) Legislative control
- (D) Doctrine of lifting of Veil

39. इन री देहली लॉज एक्ट वाद के अनुसार, विधायिका अपनी-

- (A) आवश्यक विधायिनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती है
- (B) अपनी आवश्यक विधायिनी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है
- (C) केवल आनुषंगिक विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन हो सकता है
- (D) दोनों (B) और (C) सही है

40. कार्यपालिका के कार्यों का वर्गीकृत किया जा सकता है-

- (A) स्वविवेकीय कार्यों में
- (B) अर्द्ध-न्यायिक कार्यों में
- (C) प्रत्यायोजित विधायी कार्यों में
- (D) उपरोक्त सभी में

41. विधायिका द्वारा कौन से कार्य को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है?

- (A) अधिनियम की प्रारम्भिक तिथि
- (B) सम्मिलन तथा अपवर्जन खंड
- (C) वर्तमान विधियों का लागू रहना
- (D) आवश्यक विधायी कार्य

42. निम्न में से कौन प्रत्यायोजित विधायन पर नियन्त्रण नहीं है-

- (A) अधिकारातीत का सिद्धान्त
- (B) न्यायिक नियन्त्रण
- (C) विधायी नियन्त्रण
- (D) घूँघट उठाने का सिद्धान्त

43. Henry VIII clause is a-
- (A) Removal of difficulties clause in a legislation
 - (B) Very wide and authorizes the executive in name of removal of difficulties to modify even the parent act or any other act
 - (C) Both (A) and (B) are true
 - (D) Promoter of democracy in administration
44. Henry VIII clause in name of removal of difficulties in implementation of a legislation gives so much power to the executive that it can fiddle with essential legislative powers and hence it is indicative of executive autocracy. The state refers to view of -
- (A) Lord Hewart
 - (B) Lord Acton
 - (C) Ivor jennings
 - (D) Lord Halsbury
45. Choose the incorrect option-
The essential legislative functions are-
- (A) Repeal of law
 - (B) Removal of difficulties
 - (C) Retrospective operation of an Act
 - (D) Framing of rules

43. हेनरी अष्टम खण्ड है-
- (A) विधायन की बाधाओं को हटाने वाला खंड
 - (B) बहुत विस्तृत होता है तथा कार्यपालिका को विधायन की बाधाओं को हटाने के नाम पर मूल विधायन या अन्य किसी विधायन को परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है
 - (C) (A) और (B) दोनों सही है
 - (D) प्रशासन में लोकतन्त्र को बढ़ाने वाला है
44. हेनरी अष्टम खण्ड कार्यपालिका को विधायन को लागू करने में आई बाधाओं को हटाने के नाम पर इतनी असीमित शक्ति देता है कि वह आवश्यक विधायी शक्ति, शक्तियों को दुरुपयोग करने लगा जो कि कार्यपालिका तानाशाही का द्योतक है। यह मत है -
- (A) लार्ड हीवर्ट का
 - (B) लार्ड ऐक्टन का
 - (C) आइवर जेनिंग्स का
 - (D) लार्ड हेल्सबरी का
45. निम्न में से गलत विकल्प चुनें-
आवश्यक विधायी कार्य है -
- (A) विधि का निरसन
 - (B) बाधाओं को हटाना
 - (C) किसी अधिनियम का पूर्ववर्ती तिथि से लागू होना
 - (D) नियमों को बनाना

46. Judicial control over delegated legislative can be exercised by the test of -
 (A) Substantive ultra vires
 (B) Procedural ultra vires
 (C) Both substantive and procedural ultra vires
 (D) Exigency of legislatures and its implementation
47. Choose the best option—
 A delegated legislation made in compliance of un constitutional point Act is-
 (A) Valid
 (B) Invalid
 (C) Invalid being substantively ultra vires
 (D) None of the above
48. Exclusion of judicial Review from delegative legislation makes it -
 (A) Invalid being substantively ultra vires
 (B) Valid
 (C) Partially invalid
 (D) Partially valid
49. In Lohia Machines Vs Union of India AIR 1985 SC. case the supreme court observed, “ If a rule made by a rule making authority is out side the scope of its power then the rule made by it is-
 (A) Null and void
 (B) Voidable
 (C) Depending upon situation either void or voidable
 (D) Subject ot ratification by parent Authority
46. प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियन्त्रण स्थापित किया है जिस कसौटी द्वारा, वह है—
 (A) मूल अधिकारातीत कसौटी
 (B) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत कसौटी
 (C) दोनों मूल तथा अधिकारातीत कसौटी
 (D) अधिनियम की अपरिहार्यतः एवं क्रियान्वयन कसौटी
47. सर्वोत्कृष्ट विकल्प चुनें—
 एक प्रत्यायोजित विधायन जो कि असंवैधानिक मूल अधिनियम के अनुपालन में बनाया गया हो, होगा—
 (A) विधिमान्य
 (B) अविधिमान्य
 (C) अविधिमान्य क्योंकि मूलतः अधिकारातीत होने के कारण
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
48. प्रत्यायोजित विधायन को न्यायिक पुनर्विलोकन से अपवर्जित किये जाने पर वह होगा—
 (A) अविधिमान्य, मूल अधिकारातीत होने के कारण
 (B) विधिमान्य
 (C) आंशिक अविधिमान्य
 (D) आंशिक विधिमान्य
49. लोहिया मशीनन्स बनाम भारत संघ AIR 1985 SC. में उच्चतम न्यायालय ने यह कथन दिया, “यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने अपनी प्राधिकारिता से परे जाकर नियम बनाया हो तो ऐसा नियम होगा—
 (A) निरर्थक एवं शून्य
 (B) शून्यकरणीय
 (C) परिस्थिति अनुसार शून्य या शून्यकरणीय
 (D) मूल प्राधिकारी के अनुसमर्थन के अधीन

50. If the parent Act itself delegates legislative power to the delegate unconstitutionally who according makes the rules and regulations for its implementation. If the parent authority later ratifies such rules and regulation then they be come-
- (A) Valid
 - (B) Still remain invalid
 - (C) Ratification of unconstitutional authority by parent Act is in itself ultra vires and void
 - (D) Both (B) and (C) are true
51. When a delegated legislation fails to comply with certain procedural requirements prescribed by the parent Act then such delegated legislation is-
- (A) Substantially ultra vires
 - (B) Procedurally ultra vires
 - (C) Substantially procedurally ultra vires
 - (D) None of the above
52. The rules made in violation of mandatory provisions of the parent Act are-
- (A) Void and invalid
 - (B) Voidable and invalid
 - (C) Voidable subject to ratification by parent Act
 - (D) Partially void and partially invalid
53. The delegated legislation when published takes effect-
- (A) From the date of publication
 - (B) From date fixed in the delegated legislation it self
 - (C) From post publication date
 - (D) From the date prescribed by parent Act
50. यदि मूल अधिनियम स्वयं असंवैधानिक रूप से विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन करता है, जिसके अनुसरण में डेलीगेट नियम और विनियमन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बना देता है बाद में यदि मूल प्राधिकारी ऐसे नियम और विनियमन का अनुसमर्थन कर देता है तब वे होंगे-
- (A) विधिमान्य
 - (B) अभी भी अविधिमान्य
 - (C) असंवैधानिक प्राधिकारणता को मूल अधिनियम द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होने पर वह अधिकारातीत और शून्य होगा
 - (D) (B) और (C) दोनों सही है
51. जब कोई प्रत्यायोजित विधायन मूल अधिनियम द्वारा विहित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन नहीं करता तो बना हुआ प्रत्यायोजित विधायन होगा-
- (A) मूलतः अधिकारातीत
 - (B) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत
 - (C) मूलतः प्रक्रियात्मक अधिकारातीत
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
52. मूल अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर बनाये गये नियम होंगे-
- (A) शून्य तथा अविधिमान्य
 - (B) शून्यकरणीय तथा अविधिमान्य
 - (C) शून्यकरणीय तथा मूल अधिनियम के अनुसमर्थन के आधीन
 - (D) अंशतः शून्य तथा अंशतः अविधिमान्य
53. प्रत्यायोजित विधायन जिसका प्रकाशन हो जाता है प्रभावी होगा-
- (A) प्रकाशन की तिथि से
 - (B) प्रत्यायोजित विधायन में निर्धारित तिथि से
 - (C) प्रकाशन के बाद की तिथि से
 - (D) उस तिथि से जो मूल अधिनियम में निर्धारित की गयी हो

54. Non publication and non consultation with interested persons make the delegated legislation-
- (A) Procedurally ultra vires
 - (B) Substantially ultra vires
 - (C) Both substantially and procedurally ultra vires
 - (D) None of the above
55. Government liability in torts committed by its servants be is based fundamentally on the principle of-
- (A) Vicarious liability
 - (B) Strict liability
 - (C) Absolute liability
 - (D) All of the above
56. The principle of vicarious liability is traditionally based on the maxim-
- (A) One who acts through other acts himself
 - (B) Respondent superior
 - (C) An act of an agent-binds the principal
 - (D) All the above
57. The modern concept of vicarious liability is based on-
- (A) Social convenience
 - (B) General principle of justice
 - (C) Both on social convenience and general principle of justice
 - (D) Respondent superior

54. बिना प्रकाशन तथा हितयुक्त व्यक्तियों के परामर्श के अभाव में प्रत्यायोजित विधायन होगा-
- (A) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत
 - (B) मूल अधिकारातीत
 - (C) मूल तथा प्रक्रियात्मक अधिकारातीत दोनों
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
55. सरकार का दायित्व उसके सेवको द्वारा किए गये अपकृत्यों के लिए मूलतः आधारित है-
- (A) प्रतिनिहित दायित्व के सिद्धान्त पर
 - (B) कठोर दायित्व सिद्धान्त पर
 - (C) आत्यान्तिक दायित्व सिद्धान्त पर
 - (D) उपरोक्त सभी पर
56. प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धान्त किस परंपरागत सूक्ति पर आधारित है-
- (A) जो कोई किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कर्ता है कार्य का
 - (B) प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा
 - (C) अभिकर्ता का कार्य मालिक को आबद्ध करता है
 - (D) उपरोक्त सभी
57. प्रतिनिहित दायित्व की आधुनिक संकल्पना आधारित है-
- (A) सामाजिक सुविधा पर
 - (B) न्याय के सामान्य सिद्धान्त पर
 - (C) दोनों सामाजिक सुविधा पर तथा न्याय के सामान्य सिद्धान्त पर
 - (D) प्रधान व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा पर

58. By passing of Crown Proceeding Act. of 1947 in Britain-
- (A) Sovereign immunity of king for wrongful acts ended and liability established
 - (B) The king can do no wrong maxim was blown away
 - (C) State was now liable for wrongful torts of its servants
 - (D) All the above are true
59. The tortious liability of central or state governments for the torts committed by its servants is mentioned in-
- (A) Article 300 (1) of the constitution
 - (B) Article 299 of the constitution
 - (C) Article 278 of the constitution
 - (D) Article 21 of the constitution
60. In the famous P&O steam navigation company Vs secretary of state case-
- (A) Distinction was made between sovereign and non sovereign functions of the government
 - (B) For sovereign functions the state had absolute immunity
 - (C) For non sovereign state was made liable as a private citizen
 - (D) All the above are correct

58. ब्रिटेन में क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के पारित होने से-
- (A) राजा की दोषपूर्ण कार्यों के संबंध में संप्रभुता उन्मुक्ति समाप्त हो गयी
 - (B) "राज्य कोई गलती कर ही नहीं सकता" सूक्ति विलुप्त हो गयी
 - (C) राज्य अब अपने सेवकों के दोषपूर्ण अपकृत्यों के लिए दायी होगा
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
59. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों का अपकृत्य दायित्व जो उसके सेवकों के दोषपूर्ण अपकृत्यों के लिए संविधान के जिस अनुच्छेद में वर्णित है, वह है-
- (A) अनुच्छेद 300(1) संविधान का
 - (B) अनुच्छेद 299 संविधान का
 - (C) अनुच्छेद 278 संविधान का
 - (D) संविधान का अनुच्छेद 21
60. प्रसिद्ध पी० एण्ड ओ० स्टीम नेवीगेशन कम्पनी बनाम सचिव, भारत राज्य के वाद में-
- (A) सरकार के संप्रभु तथा गैर संप्रभु कार्यों में अन्तर किया गया
 - (B) संप्रभु कार्यों के लिए राज्य को पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है
 - (C) गैर संप्रभु कार्यों के लिए राज्य प्राईवेट नागरिक के समान दायी है
 - (D) उपरोक्त सभी सही है

61. In State of Rajasthan Vs Vidhyawati. The Supreme Court of India held-

- (A) State vicariously liable for the tortious (rash and negligent acts) acts of its servants
- (B) Doctrine of absolute sovereign immunity has no place in social welfare state
- (C) Public interests demands state to be liable vicariously to for torts of servants
- (D) All the above are true

62. In Kasturilal Vs State of U.P. the decision in the Vidhyawati's case was-

- (A) Affirmed
- (B) Reversed
- (C) Sovereign and non sovereign functions doctrine and consequent sovereign immunity doctrine was restored
- (D) Both (B) and (C) are correct

63. The cases decided by supreme Court Prior and post kasturilal judgement were by smaller benches and there for technically still today the kasturilal case judgements-

- (A) Valid and law on the point
- (B) Doctrine of sovereign immunity still holds ground
- (C) Later Progressive Judgements are not binding precedent
- (D) All the above are correct

61. राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती के वाद में उच्चतम न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया—

- (A) राज्य अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों (असावधानी एवं लापरवाह कृत्यों) के प्रतिनिहित दायित्व के अन्तर्गत दायी होगा
- (B) आत्यांतिक संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त का एक समाज—कल्याणकारी राज्य में कोई स्थान नहीं है
- (C) लोक हित के दृष्टिगत भी राज्य को अपने सेवकों के अपकृत्य के लिए दायी होना चाहिए
- (D) उपरोक्त सभी सत्य है

62. कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में विद्यावती वाद के निर्णय को—

- (A) संपुष्ट किया गया
- (B) पलट दिया गया
- (C) संप्रभु और गैर संप्रभु कार्यों के वर्गीकरण सिद्धान्त को अपनाया गया तथा संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त को पुनः स्थापित किया गया
- (D) (B) और (C) दोनों सही है

63. उच्चतम न्यायालय द्वारा कस्तूरीलाल वाद के निर्णय के पूर्व तथा पश्चात वादों का निर्णय अपेक्षाकृत छोटी पीठ द्वारा किया गया अतः तकनीकी रूप से कस्तूरी लाल वाद का निर्णय है अभी भी—

- (A) विधिमान्य और विषय पर विधि
- (B) संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त अभी भी विराजमान है
- (C) पश्चातवर्ती निर्णीत वाद के निर्णय बाध्यकारी पूर्व निर्णय नहीं है
- (D) उपरोक्त सभी सही है

64. The social welfare nature of state Report of law Commission and post-Kasturilal cases decided by Supreme Court point that-

- (A) Distinction between sovereign and non sovereign functions should be done away with
- (B) Encluding exception case of defence, foreign relation etc state should be held liable for tort of its sewas
- (C) Both (A) and (B) are true
- (D) (A) is true but (B) is false

65. Choose best option-

Now for constitutional Torts (Violation of fundamental Rights) Committed by Public servants against citizens in course of duty the supreme court in many cases has held-

- (A) State vicarious liable and awarded compensation to victims
- (B) State not vicarious liable
- (C) No compensation for sovereign Acts is payable
- (D) Sovereign Immunity doctrine has still relevance

66. The contractual liability of the central Government and the state Governments is recognized by the constitution under-

- (A) Article 294
- (B) Article 298
- (C) Article 299
- (D) Under all the above Articles 294, 298 and 299

64. राज्य की समाज कल्याणकारी प्रकृति, लॉ कमीशन रिपोर्ट तथा कस्तूरीलाल वाद के पश्चातवर्ती निर्णीत वादों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इंगित करते हैं कि—

- (A) संप्रभु तथा गैर-संप्रभु कार्यों का वर्गीकरण समाप्त हो
- (B) रक्षा, विदेशी संबंध इत्यादि अपवादों को छोड़कर राज्य अपने सेवकों के अपकृत्यों के दायी हो
- (C) दोनों (A) और (B) सही हैं
- (D) (A) सही है और (B) गलत है

65. सर्वोत्कृष्ट विकल्प चुनें—

अब यदि राज्य कर्मचारियों द्वारा सेवा के दौरान नागरिकों के विरुद्ध संवैधानिक अपकृत्य कारित किये जाते हैं (मूल अधिकारों का हनन) तो उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में निर्णीत किया है कि—

- (A) राज्य प्रतिनिहित दायित्व के अधीन दायी होगा तथा पीड़ितों को प्रतिकर भी देगा
- (B) राज्य प्रतिनिहित दायित्व से दायी नहीं है
- (C) संप्रभु कार्यों के लिए कोई भी प्रतिकर नहीं देय होगा
- (D) संप्रभु उन्मुक्ति सिद्धान्त अभी भी समीचीन है

66. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का संविदात्मक दायित्व को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है—

- (A) अनुच्छेद 294 में
- (B) अनुच्छेद 298 में
- (C) अनुच्छेद 299 में
- (D) उपरोक्त सभी अनुच्छेदों 294, 298 तथा 299 में

67. The provision of Act 299 (1) are-
- (A) Mandatory and not directory in nature
 - (B) They are not more formalities but they protect the Governments against unlawful contractors
 - (C) Article 299 (1) prescribes the mode or manner of entering and executing Governmental Contracts
 - (D) All the above are correct
68. If the provisions of Article 299(1) are complied with then the contract shall be-
- (A) Valid and binding upon the Government
 - (B) Such contract can be enforced in state interest and Government can also be sued
 - (C) Both (A) and (B) are correct
 - (D) In case of non compliance of Provisions Government can by ratification adopt the contract.
69. Which among the following is other name of natural justice?
- (A) Substantial Justice
 - (B) Fundamental Justice
 - (C) Fair play in administrative action
 - (D) All the above

67. अनुच्छेद 299 (1) के प्रावधान है-
- (A) आज्ञात्मक न कि निर्देशात्मक
 - (B) ये मात्र औपचारिकता नहीं है तथा इनका उद्देश्य अवैध ठेकेदारों से राज्य को सुरक्षा प्रदान करना होता है
 - (C) अनुच्छेद 299 (1) वस्तुतः सरकारी संविदाओं को कारित तथा क्रियान्वित करने के तरीके को बताता है
 - (D) उपरोक्त सभी सही है
68. यदि अनुच्छेद 299(1) के प्रावधानों का अनुपालन हो गया हो तो कारित संविदा-
- (A) वैध होगी तथा सरकार पर बाध्यकारी होगी
 - (B) ऐसी संविदा राज्यहित में प्रवर्तित की जा सकेगी तथा सरकार के विरुद्ध भी वाद संस्थित हो सकेगा
 - (C) (A) और (B) दोनों सही है।
 - (D) प्रावधानों का अनुपालन न होने पर सरकार अनुसमर्थन कर संविदा को मान्यता दे सकती है
69. निम्न में कौन नैसर्गिक न्याय का वैकल्पिक नाम है?
- (A) सारवान न्याय
 - (B) मूलभूत न्याय
 - (C) प्रशासनिक कार्यों में स्वच्छ (निष्पक्ष) प्रकटीकरण
 - (D) उपरोक्त सभी

70. The concept of Natural justice cannot be defined in enactitude yet it imports within its substance certain elements that appeal to the inner conscience of Human by as a whole. The elements included are-

- (A) Moral considerations of highest form
- (B) Sense of Justice while taking action
- (C) Fairness in deed and action
- (D) All the above

71. "No body can be a judge in his own cause" means and refers to-

- (A) Rule against bias
- (B) Right of hearing before adjudication
- (C) Both (A) and (B) are true
- (D) Neither (A) nor (B) is correct

72. Rule of Bias is operative against-

- (A) Pecuniary Bias
- (B) Personal Bias
- (C) Departmental Bias or Bias as to subject matter
- (D) On All the above

73. Dr Bonham's case is related to-

- (A) Pecuniary bias
- (B) Personal bias
- (C) Departmental Bias
- (D) Subject matter Bias

70. नैसर्गिक न्याय को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता परन्तु वह अपने सार में ऐसे तत्वों को समावेशित करता है जो कि संपूर्ण मानवता की अन्तर्चेतना को छूती है। समावेशित तत्व है—

- (A) उच्चतम स्तर के नैतिक मानक
- (B) कार्यवाही करते वक्त न्यायप्रियता की भावना
- (C) कार्य एवं स्वाभाव में निष्पक्षता
- (D) उपरोक्त सभी

71. "कोई भी व्यक्ति स्वयं के वाद में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।" कथन का अर्थ एवं आशय है—

- (A) पक्षपात के विरुद्ध नियम से
- (B) निर्णय देने से पूर्व सुनवाई के अधिकार से
- (C) (A) और (B) दोनों सही है
- (D) न तो (A) और न ही (B) सही है

72. 'पक्षपात के विरुद्ध' नियम लागू होता है—

- (A) आर्थिक पक्षपात के विरुद्ध
- (B) व्यक्तिगत पक्षपात के विरुद्ध
- (C) विभागीय पक्षपात अथवा विषयवस्तु संबंध पक्षपात के विरुद्ध
- (D) उपरोक्त सभी पर

73. "डॉ० बोनहम" का वाद संबंधित था—

- (A) आर्थिक पक्षपात से
- (B) व्यक्तिगत पक्षपात से
- (C) विभागीय पक्षपात से
- (D) विषय-वस्तु संबंधी पक्षपात से

74. 'Audialteram partem' means-
(A) Listening to the appeal
(B) Right of fair hearing
(C) Right to know reasons of decision
(D) Decency in pronouncing a judgement

75. Principle of natural justice are not applicable against which of the following actions-
(A) rule making actions
(B) Quasi judicial actions
(C) Judicial process
(D) Administrative actions

76. Principles of Natural Justice do not supplant the law of the land but supplement it" This was held in the case of-
(A) Menaka Gandhi Vs Union of India
(B) A.K. Kraipak Vs Union of India
(C) State of U.P. Vs Mohd Nooh
(D) A.K. Gopalan Vs state of Madras

77. When personal hearing is given by one officer and order is passed by another officer the principle of natural justice violated is-
(A) Right to hearing
(B) rule against bias
(C) Reasoned decision
(D) Both (B) and (C) are true

74. 'ऑडी ऑलटरम पार्टम" का अर्थ है-
(A) अपील को सुनना
(B) उचित सुनवाई का अवसर
(C) निर्णय के आधारों को जानने का अधिकार
(D) निर्णय देते हुए शालीनता बनाए रखना

75. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त निम्न में से किन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे-
(A) नियम निर्माण की कार्यवाही पर
(B) अर्धन्यायिक कार्यवाहियों पर
(C) न्यायिक प्रक्रिया पर
(D) प्रशासनिक कार्यों पर

76. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त किसी विधि को प्रतिस्थापित न कर उसे परिपूर्ण करते हैं। यह कहा गया था जिस वाद में वह है-
(A) मेनका गाँधी बनाम भारत संघ
(B) ऐंके० क्रेपाक बनाम भारत संघ
(C) उ०प्र० राज्य बनाम मोहम्मद नूह
(D) ऐंके० गोपालन बनाम मद्रास राज्य

77. जब व्यक्ति सुनवाई का अवसर एक अधिकारी द्वारा दिया जाता और आदेश दूसरे अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, तब नैसर्गिक न्याय के किस नियम का उल्लंघन होता है-
(A) सुनवाई के अवसर का
(B) पक्षपात के विरुद्ध नियम का
(C) कारण युक्त निर्णय का
(D) (B) और (C) दोनों सही हैं

78. Choose the best option-
‘Reasoned Decision’ means-
- (A) A Party to a dispute has a right not only to know the decision of a case but also the reason of the decision
 - (B) Right to know decision of the case
 - (C) Right to know reason of the decision
 - (D) Compliance to principle of Natural justice
79. A writ petition can be filed in which of the following Courts-
- (A) In Supreme Court
 - (B) In High Court
 - (C) In District Court
 - (D) In Both Supreme Court and High Court
80. The writ jurisdiction of supreme and High Courts of the state is contained in which of the following Articles of the constitution-
- (A) Articles 32 and 217
 - (B) Articles 32 and 266
 - (C) Articles 32 and 226
 - (D) Articles 136 and 226
81. Which among the following writs is curative in nature-
- (A) Writ of Mandamus
 - (B) Writ of Quo-warranto
 - (C) Writ of Habeas Corpus
 - (D) Writ of Certiorari

78. सर्वोत्कृष्ट विकल्प को चुने-
“सकारण निर्णय” का अर्थ है –
- (A) विवाद के पक्षकार को वाद का निर्णय जानने के अधिकार के साथ निर्णय का कारण जानने का भी अधिकार
 - (B) वाद का निर्णय जानने का अधिकार
 - (C) निर्णय के कारण को जानने का अधिकार
 - (D) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करना
79. एक रिट याचिका निम्न में से किन न्यायालयों में दाखिल की जा सकती है-
- (A) उच्चतम न्यायालय में
 - (B) उच्च न्यायालय में
 - (C) जिला न्यायालय में
 - (D) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में
80. उच्चतम न्यायालय तथा राज्य के उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता संविधान के किन अनुच्छेदों में समाहित है-
- (A) अनुच्छेद 32 और 217 में
 - (B) अनुच्छेद 32 और 266 में
 - (C) अनुच्छेद 32 और 226 में
 - (D) अनुच्छेद 136 और 226 में
81. निम्न में कौन सी रिट उपचारात्मक प्रकृति की होती है-
- (A) परमादेश
 - (B) अधिकारपृच्छा
 - (C) बन्दी प्रत्यक्षीकरण
 - (D) उत्प्रेषण

82. The writ based on the principle of 'Prevention is better than cure' is-
- (A) Prohibition
 - (B) Mandamus
 - (C) Certiorari
 - (D) None of the above
83. When any public authority on demand refuses to carry out his public duty, then against him which writ can be filed against him-
- (A) Mandamus
 - (B) Quo-warranto
 - (C) Prohibition
 - (D) Certiorari
84. A person usurping a public office without having right authority to do so then proper writ against him would be-
- (A) Quo-warranto
 - (B) Certiorari
 - (C) Both Quowarranto and certiorari
 - (D) Prohibition
85. A subordinate having no jurisdiction takes a case for hearing and passes preliminary order on some issues in favour of the plaintiff and reserves other issues for next hearing. The defendant can get remedy by which of the writ/writs-
- (A) By writs of certiorari and prohibition respectively
 - (B) Writs of prohibition and certiorari respectively
 - (C) Only from certiorari
 - (D) Only from prohibition

82. कौन सी रिट "उपचार से सावधानी भली" सिद्धान्त पर आधारित है-
- (A) प्रतिषेध
 - (B) परमादेश
 - (C) उत्प्रेषण
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
83. जब कोई लोक प्राधिकारी माँग करने पर भी अपने लोक कर्तव्य का पालन न करे, तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट दाखिल की जा सकती है-
- (A) परमादेश
 - (B) अधिकारपृच्छा
 - (C) प्रतिषेध
 - (D) उत्प्रेषण
84. एक व्यक्ति जो बिना अधिकार अथवा प्राधिकार के एक लोक पद पर काबिज हो जाता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट उपयुक्त रिट दाखिल होगी-
- (A) अधिकार पृच्छा
 - (B) उत्प्रेषण
 - (C) अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण दोनों
 - (D) प्रतिषेध
85. एक अधीनस्थ न्यायालय बिना अधिकारिता के वाद की सुनवाई करता है। सुनवाई के दौरान कुछ मुद्दों पर वादी के पक्ष में प्रारंभिक आदेश पारित कर देता है तो शेष वाद बिन्दुओं को अगली सुनवाई हेतु टाल देता है प्रतिवादी कौन सी रिटों से उपचार प्राप्त कर सकेगा-
- (A) क्रमशः उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध से
 - (B) क्रमशः प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण से
 - (C) केवल उत्प्रेषण से
 - (D) केवल प्रतिषेध से

86. Rule of Locusstendei is not applicable to-
- (A) Private litigations
 - (B) Public interest litigation
 - (C) Arbitration proceedings
 - (D) To both (A) and (C)
87. Public interest litigation may be filed by a public spirited citizens for-
- (A) Protecting the rights and interest of economically poor uneducated and deprived section of society in case of violation of their fundamental rights cause
 - (B) Public cause and public interest matters of great importance
 - (C) Public cause and not for publicity or political gains
 - (D) All the above are correct
88. The institution of ombudsman originated in 1809 at-
- (A) Sweden
 - (B) France
 - (C) Germany
 - (D) Switzerland
86. वाद दाखिल करने में हित संबंधी औपचारिकता का नियम लागू नहीं होता है—
- (A) प्राइवेट विवादों पर
 - (B) लोक हित वाद पर
 - (C) मध्यस्थम कार्यवाहियों पर
 - (D) दोनों (A) और (C) पर
87. लोक हित वाद किसी ऐसे नागरिक द्वारा जा कि लोक भावना से प्रेरित हो दाखिल किया जा सकता है—
- (A) आर्थिक रूप से विपन्न, अशिक्षित तथा समाज के वंचित वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु
 - (B) लोक निमित्त तथा जन हित संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के लिए
 - (C) लोक निमित्त हेतु न कि व्यक्तिगत वाह—वाही तथा राजनीतिक लाभ हेतु
 - (D) उपरोक्त सभी सही हैं
88. 'ओम्बुड्समैन' संस्था का प्रादुर्भाव 1809 में हुआ था—
- (A) स्वीडन में
 - (B) फ्रांस में
 - (C) जर्मनी में
 - (D) स्विट्जरलैंड में

89. The function of Ombudsman is to-
- (A) Conduct enquiry with regard to public grievances against abuse of administrative discretion, corruption related practices, misconduct and negligence of duties by public official and public servants and give recommendations.
 - (B) Raise matters of public importance in Media
 - (C) To institute writ petition against corrupt officials and peoples representatives
 - (D) All the above
90. The Lokpal and Lokayuktas Bill was passed by Indian Parliament 45 years after its introduction in Loksabha on the date-
- (A) 18th December 2013 with presidential assent on 1st January 2014
 - (B) 10th December 2013 with president assent on the same date
 - (C) 1st January 2013 and president assent on the same date
 - (D) None the above

89. ओम्बुड्समैन का कार्य है—
- (A) लोक शिकायतों पर जो कि प्रशासनिक अधिकार्यों तथा लोक सेवकों द्वारा विवेकीय शक्तियों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार संबंधित कार्यप्रणाली, कदाचार तथा उनके द्वारा कर्तव्यों में घोर लापरवाही इत्यादि मामलों की जाँच करना तथा अपनी अनुशंसा समाधान हेतु करना
 - (B) मीडिया में जन सामान्य के महत्वपूर्ण मामले उठाना
 - (C) भ्रष्ट अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल करना
 - (D) उपरोक्त सभी
90. लोकपाल तथा लोकायुक्त विधियेक लोकसभा में प्रथम बार प्रस्तुत होने के 45 वर्ष पश्चात संसद द्वारा पारित किया गया—
- (A) 18 दिसम्बर 2013 को, जिसे राष्ट्रपति को सम्मति, 1 जनवरी 2014 को प्राप्त हुई
 - (B) 10 दिसम्बर 2013 को तथा उसी दिन राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई
 - (C) 1 जनवरी 2013 को तथा उसी दिन राष्ट्रपति सम्मति प्राप्त हुई
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

91. The institution of lokpal and lokayuktas has in India has a-
- (A) Constitutional status
 - (B) Only a statutory status
 - (C) Both constitutional and statutory status
 - (D) Neither constitutional nor statutory status
92. The office of Prime minister now-
- (A) Comes under the purview of lokpal enquiry
 - (B) Does not comes under the lokpal enquiry
 - (C) Office of Prime minister does not but other Central Minister come under Lokpals enquiry
 - (D) None of the above
93. In exercise of judicial Review power by the Supreme Court and High Court with regard to Administrative actions they use their-
- (A) Jurisdiction under Article 32
 - (B) Jurisdiction under Article 226
 - (C) Jurisdiction under Article 32 by Supreme Court and Jurisdiction under Article 226 by High Courts
 - (D) None of the above
91. भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्तों की संस्था को प्राप्त है—
- (A) संवैधानिक हैसियत
 - (B) सांविधिक हैसियत
 - (C) दोनों संवैधानिक तथा सांविधिक हैसियत
 - (D) न ही संवैधानिक हैसियत और न ही सांविधिक हैसियत
92. प्रधानमंत्री का पद अब—
- (A) लोकपाल की जाँच के दायरे में है
 - (B) लोकपाल के जाँच दायरे से बाहर है
 - (C) प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रीय मंत्री लोकपाल जाँच के दायरे में होंगे
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
93. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते वक्त वे प्रयोग करते हैं—
- (A) अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का
 - (B) अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का
 - (C) उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 की अधिकारिता का
 - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

94. The most frequently issued writs by Supreme Court and High Courts to correct. Administrative mal functioning negligence-

- (A) Mandamus and prohibition
- (B) Quowarranto and prohibition
- (C) Mandamus and Quowarranto
- (D) None of the above

95. Choose the best option -

A Public Corporation is a hybrid entity because it has-

- (A) Features of a government department
- (B) Features of a commercial company
- (C) Having some features of a government department and some features of a business company

(D) Is a constitutional body

96. A public corporation is-

- (A) Created by statute and as such has legal personality
- (B) It can sue and be sued and has contractual tortious and criminal liability
- (C) Is autonomous in character
- (D) All the above are true

94. प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही तथा दुरुपयोग को सही करने के लिए उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा बहुधा जारी की जाने वाली रिट होती है-

- (A) परमादेश तथा प्रतिषेध
- (B) अधिकारपृच्छा तथा प्रतिषेध
- (C) परमादेश तथा अधिकारपृच्छा
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

95. सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने-

एक लोग निगम एक मिश्रित निकाय है क्योंकि-

- (A) इसमें सरकारी विभाग के लक्षण होते हैं
- (B) वाणिज्यिक कम्पनी के लक्षण होते हैं
- (C) थोड़े लक्षण सरकारी विभाग तथा थोड़े लक्षण वाणिज्यिक कंपनी के होते हैं
- (D) एक संवैधानिक निकाय है

96. एक लोक निगम-

- (A) का निर्माण अधिनियम द्वारा होता है अतः इसका अपना विधिक व्यक्तित्व होता है
- (B) यह वाद संस्थित कर सकता है तथा इसके विरुद्ध भी वाद संस्थित हो सकता है अतः इसके संविदात्मक, अपकृत्य संबंधी तथा आपराधिक दायित्व होते हैं
- (C) स्वायत्तशासी प्रकृति की होती है
- (D) उपरोक्त सभी सत्य हैं

97. Which among the following is not a Public corporation-
- (A) Reserve Bank of India
 - (B) Damodar Valley corporation
 - (C) Tata Services consultancy
 - (D) Road Transport corporation
98. Now all the public corporations are considered to be-
- (A) An instrumentality of the state and hence state as defined in Article 12 of the constitution
 - (B) Are not state under Article 12 of the constitution
 - (C) Both state under Article 12 of the constitution and a legal person
 - (D) (A) and (C) both are true
99. The Principle of Promissory estoppel-
- (A) Is based on principle of equity
 - (B) Is much wider in scope and application as compared to estoppel defined under section 115 of Indian Evidence Act
 - (C) States that a promise made must be fulfilled and honoured and can not be denied later to the detriment of other person
 - (D) All the above are true
100. A given promise, which goes against the public interest and is against public policy is-
- (A) Enforceable by principle of promissory estoppel
 - (B) Not enforceable by principle of promissory estoppel
 - (C) Partially enforceable
 - (D) Partially non enforceable

97. निम्न में से कौन लोक निगम नहीं है—
- (A) भारतीय रिजर्व बैंक
 - (B) दामोदर घाटी कारपोरेशन
 - (C) टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज
 - (D) सड़क परिवहन कारपोरेशन
98. अब सभी लोक निगम माने जाते हैं—
- (A) राज्य उपक्रम अतः संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत 'राज्य' है
 - (B) संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य नहीं है
 - (C) संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य तथा विधिक व्यक्ति भी
 - (D) (A) और (C) दोनों सही हैं
99. 'वचनीय विबन्ध' का सिद्धान्त—
- (A) साम्या पर आधारित है
 - (B) सीमा तथा प्रयोज्यता में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित 'विबन्ध' से अधिक व्यापक है
 - (C) कहता है दिये गये वचन को पूरा करना, तथा सम्मान देना चाहिए और बाद में उससे मुकरा नहीं जा सकता दूसरे व्यक्ति का हानि पहुँचाने के दृष्टि से
 - (D) उपरोक्त सभी सही हैं
100. एक दिया गया वचन जो लोक हित तथा लोक नीति के विरुद्ध हो, तब वह—
- (A) वचनीय विबन्ध सिद्धान्त के अनुसार प्रवर्तनीय होगा
 - (B) वचनीय विबन्ध सिद्धान्त पर अप्रवर्तनीय होगा
 - (C) आंशिक प्रवर्तनीय होगा
 - (D) आंशिक अप्रवर्तनीय होगा

Rough Work / रफ कार्य

DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

Note: On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.